

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

2016/00069

APP-A
Crim-18/8

27/8/16

22/9

3.11

9.3.17

जज अदालत आरिठ जिला कलकत्ता 22 मुकाम सुसुब्र

अरविन्द कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद मिश्र बनाम पद्म पुत्र मोतीलाल नरहड

किस्म मुकदमा निगरानीकार नं. 12 सन् 2016

तारीख हुम	हुम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुम की तामील में जारी हु
22.6.16	आज यह निगरानी कार्ड रिपोर्ट देवा डई। वकील निगरानीकार उपर। निगरानी दर्ज रजिस्ट्रार को जावे। मिलल मातहत तलख हो। गैर निगरानीकार को परिषद सम्मिलित गणल निगरानी कार्य के प्रकार तलख दिख जावे। प्रमादली वार्ड नरहड। मिलल दिनांक 11-7-16 को देवा हो।	11-7-16
11-7-16	पत्रावली पेश हुई निगरानीकार आधि उपर। मिलल मातहत तलख हो। गैर निगरानीकार को अति. सम्मन तलख बांभा. वेजा कर तलख दिमा जावे। पत्रावली वास्ते मिलल तलखी दिनांक 25/7/16 को देवा हो।	21/8
25/7/16	प्रमादली पेश डई निगरानीकार उपर। मिलल मातहत तलख कटो व गैर निगरानीकार को लफ्त। तलकाग पेश होत पर जारी हो। प्रमादली वार्ड मिलल। तलखी दिनांक 8-8-16 को देवा हो।	आरिठ-534

23/12/19

पत्रावली पेडा हुई। वकील पक्षकारान उपरिबत ।
 प्राची/गौर निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत प्राचीना
 प्राथमिक आपील का अवलोकन किया एवं
 विज्ञान अधिवक्ता उभय पक्ष को बहस
 पर मनन किया। दस्तगत प्रकरण में
 निगरानीकार द्वारा ग्राम पंचायत नरहड द्वारा
 जारी पट्टेया संख्या 88 दिनांक 20/3/2013
 को निरस्त करवाने के लिए प्रथम अपील
 पंचायत समिति चिड़ावा में की गई है।
 जो पंचायत समिति चिड़ावा द्वारा दिनांक
 11-3-2016 को अपील क्रमांक बाहर मान कर
 निरस्त कर दी गई। उल्लेख उपरान्त पंचायत
 समिति के आदेश दिनांक 11-3-2016 के
 विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।
 जबकि पहले पंचायत समिति चिड़ावा में
 प्रथम अपील होने के बाद द्वितीय अपील
 जिला परिषद डुंगर में होती।
 राज. पंचायती राज अधि. 1994 को धारा 91(4)
 में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि पंचायत
 समिति के किसी आदेश या निर्देश के विरुद्ध
 30 दिनों को अवधि में अधिभावेता रूप में
 जिला परिषद में अपील कर सकता है।
 ग्राम पंचायत के आदेशों के विरुद्ध प्रभावित
 पक्षकार के पास दो विकल्प हैं, प्रथम यह
 ग्राम पंचायत के आदेश के विरुद्ध धारा 61(1) राज.
 पंचायत अधि. 1994 के अंतर्गत 1994 के पंचायत
 समिति में अपील कर सकता है या फिर
 प्रभावित पक्षकार यह तो धारा 91 पंचायती
 राज अधि के अंतर्गत राज्य सरकार को निगरानी
 कर सकता है।

दस्तगत प्रकरण में निगरानी पंचायत
 समिति चिड़ावा द्वारा प्रथम अपील में
 पारित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत हुई
 है। जबकि राज. पंचायती राज अधि. 1994 को
 के अंतर्गत धारा 91(4) के अंतर्गत द्वितीय
 अपील जिला परिषद में होगी। ऐसी 41

राज. पंचायती राज अधि.
 1994 के अंतर्गत
 धारा 91(4)
 के अंतर्गत

दिव्याते में हम प्रकरण के तथ्यों एवं
परिस्थितियों को देखते हुये प्राचीन
गैर निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत यह
प्राचिन आपत प्रायतः स्वीकार किया
जाता है। गौश्रदा निगरानी पोषणीय
गमी होने के कारण इसी कटेज पर
रपारिज की जाती है। आदिवा
सुनापा गया। पत्रावली फैलल
मुद्दा होकर दर्ज केवर से काम
है तथा काद तकमील आदता
दारिदर दपतर है।

49
अति. विवा. कलेक्टर
मुम्बई

